



शुक्रवार तड़के प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीरा बा का निधन हो गया। निधन के बाद प्र. मंत्री की माँ के पार्थिव शरीर का गांधीनगर मुक्तिधाम शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। प्र. मंत्री ने अपने भाई के साथ उन्हें मुखानि दी। गांधीनगर के शमशान में पूरे वैदिक विधि-विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री और उनके भाईयों ने माँ हीरा बा के पार्थिव शरीर के पंचतत्व में विलीन होने से पहले उनके शरीर में घी का लेप किया। हीरा बा का पूरे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुखानि देने के समय प्र. मंत्री बहुत भावुक हो गए। अंतिम संस्कार के पहले एवं बाद में प्र. मंत्री मोदी ने अपने भाइयों से मुलाकात की। मोदी ने इससे पहले सुबह अपने भाई पंकज मोदी के घर गांधीनगर के रायता पहुंचे, जहां उनकी माँ हीरा बा रहती थीं। बाद में वे अपने भाईयों सोमभाई, प्रहलादभाई और अमृतभाई तथा उनके परिवार से मिले। इस बीच प्र. मंत्री के पंचतत्व गांव वडनगर में व्यापारियों ने हीरा बा के निधन के शोक में तीन दिनों तक बाजार बंद रखने की घोषणा की है।

प्र.मंत्री मोदी ने माँ के पार्थिव शरीर को मुखानि दी

गांधीनगर, 30 दिसंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीरा बा का पार्थिव शरीर मुक्तिधाम शमशान घाट में पंचतत्व में हुआ विलीन। मोदी ने अपने भाई के साथ उन्हें मुखानि दी। प्रधानमंत्री की माँ हीराबा मोदी का पार्थिव शरीर गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया। जहां पूरे वैदिक विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री और उनके भाईयों ने माँ हीरा बा के पार्थिव शरीर के पंचतत्व में विलीन होने से पहले उनके शरीर में घी का लेप किया। हीरा बा का पूरे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मोदी ने अपने भाई के साथ माँ के पार्थिव शरीर को मुखानि दी। मुखानि देने के समय प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए। मुक्तिधाम शमशान घाट में हीरा बा की अंत्येष्टि के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य सरकार के मंत्री, विधायकों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

प्रधानमंत्री माँ हीरा बा का अंतिम संस्कार करने के बाद शमशान घाट से राजभवन की ओर रवाना हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री को जैसे ही माँ के निधन की सूचना मिली वह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचने से पहले गुजरात के

■ प्र.मंत्री मोदी को जैसे ही माँ के निधन की खबर पता चली वे तुरंत गांधीनगर रवाना हो गये।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां मौजूद थे। मोदी हवाई अड्डे से सीधे गांधीनगर में अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर रायता पहुंचे। प्रधानमंत्री ने माँ हीराबा के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पण कर नमन किया। इसके बाद मोदी ने माँ की अर्थ को कंधा दिया। जिसके बाद हीराबा के पार्थिव शरीर को गांधीनगर के मुक्तिधाम शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की माँ हीराबा का निधन शुक्रवार तड़के साढ़े तीन बजे अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में हो गया। हीराबा की 100 वर्ष की थी। उन्हें बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अहमदाबाद के यू.एन. मेहता शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों के बड़ी संख्या में नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीरा बा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

मुर्मू ने अपने शोक संदेश में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीरा बा का सौ वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। मोदी ने 'मातृ देवो भवः' की भावना और हीरा बा के मूल्यों को अपने जीवन में डाला। (शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या "होनहार पुत्र" गुलाम नबी वापस घर लौटेंगे कांग्रेस में?

गुजरात व हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान गुलाम नबी के तेवर काफी बदले-बदले से नज़र आये थे

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। इस समय राजनैतिक हलकों में, गुलाम नबी आज़ाद की सम्भावित घरवापसी की अटकलें एवं अनुमान जोरों पर हैं। ज्ञातव्य है कि आज़ाद ने कांग्रेस के साथ 52 वर्ष के लम्बे जुड़ाव के बाद, इस साल आरम्भ में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था तथा इसके बाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बना ली थी।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों- महबूबा मुफ्ती तथा उमर अब्दुल्लाह के विपरीत, आज़ाद ने कांग्रेस के इस आव्हान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि गैर-भाजपा दलों के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में शामिल हों। लेकिन अपने राजनैतिक भविष्य पर पुनर्विचार का संकेत देते हुए, उन्होंने गुजरात एवं हिमाचल के हाल ही के चुनावों से पहले, यह जरूर कहा था कि भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा केवल कांग्रेस ही कर सकती है। उस समय उन्होंने यह स्पष्टीकरण भी दिया था कि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों का सम्बंध कांग्रेस की कमजोर व्यवस्था से था, कांग्रेस की नीतियों से नहीं। आज़ाद के इस परिष्कृत, संयमित एवं अनुशासित लहजे से प्रभावित होकर, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह यात्रा

■ गुलाम नबी ने कहा था कि, केवल कांग्रेस ही भाजपा को चुनौती दे सकती है, तथा उन्होंने कभी कांग्रेस की नीतियों का विरोध नहीं किया। उनका विरोध केवल कांग्रेस की कमजोर कार्य प्रणाली से था।

■ गुलाम नबी के बदले हुए तेवर देखकर महासचिव दिग्विजय सिंह ने उन्हें दोबारा, कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का आमंत्रण भेजा।

■ जी-23 ग्रुप के नेता भूपेंद्र सिंह हूडा व अखिलेश प्रसाद सिंह को गुलाम नबी को वापस पार्टी में लाने के प्रयास से जोड़ा गया है। अंबिका सोनी भी सक्रिय हुई हैं, तथा उन्होंने गुलाम नबी से पुनः संपर्क स्थापित किया है।

■ पर, वापसी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पार्टी से इस्तीफा देते समय गुलाम नबी ने बहुत व्यागत्मक पत्र लिखा था, सोनिया गांधी को तथा राहुल गांधी की भी खिल्ली उड़ायी थी। राहुल को "गैर गंभीर" राजनीतिज्ञ बताया था।

■ पर, कांग्रेस हाईकमान सब कुछ भूलकर उन्हें वापस लेने के मूढ़ हैं, अगर, गुलाम अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएं और खेद व्यक्त करें।

में शामिल होने के आमंत्रण के नवीनीकरण पर विचार कर रहे हैं। पूर्व जी-23 के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह तथा भूपेंद्र सिंह हूडा को संकेत दिया गया है कि वे आज़ाद को फिर से पार्टी में आने के लिये प्रेरित करें। बताया जाता है कि वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने भी आज़ाद के साथ सम्पर्क साधा है। आज़ाद यह देख रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह में, कई नेता उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके ताज़ातरीन उदाहरण (शेष पृष्ठ 5 पर)

कांग्रेस के विधायक बजट सत्र से पहले लेंगे इस्तीफे वापस

अन्यथा विधानसभा अध्यक्ष और सरकार को सदन में स्पष्ट करनी पड़ेगी अपनी स्थिति

जयपुर, 30 दिसम्बर (का.सं.)।

राजस्थान में 3 दिन तक रुककर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक लिया, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जयपुर से रवाना होने के साथ ही 25 सितंबर को इस्तीफा देने वाले विधायकों की ओर से इस्तीफा वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि प्रभारी की ओर से दिए गए संकेतों के बाद में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी विधायकों को संदेश दे दिया है कि वह विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी से मिलकर अपने इस्तीफे निजी स्तर पर जाकर वापस से लें। दरअसल 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। कांग्रेस को और विधानसभा अध्यक्ष डा. जोशी को यह स्पष्ट पड़ता

कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उनका स्टेटस क्या है। इन हालात में सत्र शुरू होते ही हंगामा होना था। यह भी बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।

प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ पहली बार राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक हुई, जो करीब ढाई घंटे से भी ज्यादा चली और गुरुवार रात 10:45 बजे तक सरकार के मंत्री प्रभारी के सामने अपनी शिकवे शिकायतें करते रहे। बताया जाता है कि 2 दिन तक चले फीडबैक कार्यक्रम के दौरान अधिकांश विधायकों, विधायक प्रत्याशियों, सांसद प्रत्याशियों और पार्टी के विधायकों ने अपनी शिकवे शिकायतें रंधावा को लेंकर नाराजगी जताई। प्रभारी रंधावा ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। तो उन्होंने सभी मंत्रियों से साफ कह

दिया था कि आपको लेकर पार्टी में खासी नाराजगी है। यदि रवैया नहीं बदला तो आने वाले दिनों में कई मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। वैसे भी चुनावी वर्ष में मंत्रिमंडल में एक फेरबदल होना तय माना जा रहा है। ऐसे में यदि मंत्रियों ने अभी भी अपने दरवाजे बंद रखे और पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतें नहीं की तो उनको हटाने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त कारण होंगे। वैसे तो प्रभारी के साथ बैठक के दौरान अधिकांश मंत्रियों ने बाहर आकर

■ इस्तीफा वापस लेने की पहल प्रभारी रंधावा की फीडबैक बैठकों का असर है?

■ इधर गुरुवार देर रात तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों के मनमुटाव और शिकवे-शिकायतें ही खुलकर सामने आईं। यही कहा कि कोई खास बात नहीं हुई और बजट को लेकर सुझाव मांगे गए थे। लेकिन हकीकत यह रही कि मंत्रियों के आपसी मनमुटाव प्रभारी के समक्ष खुलकर सामने आए। अधिकांश मंत्रियों की पीड़ा यह रही कि उनके कहने से अधिकारी काम तक नहीं करते। यही कारण रहा कि प्रभारी को कहना पड़ा कि मंत्रियों का काम विकेंद्रीकरण के हिसाब से होना चाहिए। जहां तक थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों का मैटर है, तो इसे लेकर बिना किसी नीति के सरकार को

1979 में इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के पास केवल दो राज्यों में सरकार थी

इन दोनों राज्यों, आंध्र व कर्नाटक, के मु.मंत्रियों ने, जब आँख दिखाना शुरू किया तो, इंदिरा गांधी ने दोनों राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, इस बात की बिना परवाह किये कि, तब कांग्रेस के पास किसी भी राज्य में कहीं भी सरकार नहीं रही थी

-नेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। जहाँ वर्ष 2022 पूरी तरह सज-संबर कर अलविदा कहने के लिये तैयार है तथा नया वर्ष आने को है, वहीं राजस्थान कांग्रेस को नेतृत्व ने बहुत सस्ते में निबटारा है तथा इसके लिये यह वर्ष अतीत के सबसे खराब वर्षों में से एक रहा है।

छोटे-बड़े सभी कांग्रेसजन अनिश्चितता एवं अस्थिरता एवं तौर-तरीकों से उकता चुके हैं, जिन तौर-तरीकों से अशोक गहलोत सरकार, पार्टी नेतृत्व की अक्ल करते हुये, जबरन बनी हुई है जिसके फलस्वरूप पार्टी कार्यकर्ताओं में विद्रोह की आग सुलगने, बल्कि भड़कने लगी है। यह सुनिश्चित तथ्य भी मुख्यमंत्री

अशोक गहलोत के व्यवहार एवं तौर-तरीकों से सम्बंधित ही है कि कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व इतना कमजोर कभी नहीं रहा, जितना कमजोर आज है। अनुशासनहीनता पर दृढ़ एवं कठोर रुख अपनाने में अनिश्चित, हिचकिचाहटपूर्ण तथा असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं सोनिया गांधी ने राजस्थान के मामले

और एक सोनिया गांधी हैं, जिनके पास 1979 में मात्र दो राज्य सरकारें थीं- आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक लेकिन इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने उन्हें आँखें दिखाई तो उन्होंने दोनों सरकारों को बर्खास्त कर

■ अब भी सोनिया गांधी के पास भी दो राज्यों, राजस्थान व छत्तीसगढ़, में कांग्रेस की सरकारें हैं।

■ पर, सोनिया गांधी काफी "भयभीत" रही हैं, इस दोनों राज्यों की सरकारों को कुछ भी कहने को बारे में। शायद उनको भय है कि, इन दोनों राज्यों में कुछ छेड़खानी करने पर, मुख्यमंत्री कभी भी सरकार गिरा सकते हैं।

■ यह भय राजस्थान व मु.मंत्री गहलोत के बारे में ज्यादा है।

■ हालांकि, यह सच है कि, गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कभी जीत कर नहीं आयी। अतः भाजपा को भी यह स्थिति माफिक आती है कि, हाईकमान की अनिश्चय की स्थिति में, गहलोत ही मु.मंत्री बने रहें तथा गहलोत के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरे।

को समय के भरसे छोड़ दिया है जिससे यह साफ संदेश जा रहा है कि अब उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहा है। एक इंदिरा गांधी थी, जिनके पास 1979 में मात्र दो राज्य सरकारें थीं- आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक लेकिन इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने उन्हें आँखें दिखाई तो उन्होंने दोनों सरकारों को बर्खास्त कर

दिया तथा इस बात की परवाह तक नहीं की कि उनके इस कदम का अर्थ यह होगा कि कांग्रेस की सरकार एक भी राज्य में नहीं रहेगी।

और एक सोनिया गांधी हैं, जिनके पास भी केवल दो राज्य सरकारें हैं लेकिन वे मुख्यमंत्रियों को छूने तक में डरती हैं तथा उन्हें यह आशंका रहती है

कि वे सरकार गिरा देंगे, खासतौर से अशोक गहलोत ने तो यह धमकी दे रखी है कि नेतृत्व को नीचा दिखाने वाले उनके विद्रोह के फलस्वरूप, अगर उन्हें हटाया गया तो वे सरकार गिरा देंगे। लेकिन, वे अब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम हैं क्योंकि गांधी परिवार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में बहुत ज्यादा डर रहा है।

ऐसे परिदृश्य में, पार्टी कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से किंकरतव्यमूढ़ हैं तथा वे नहीं समझ पा रहे कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा।

इस साल ने जाते-जाते यह साफ तौर पर दिखा दिया है कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी नैतिक सत्ता खो चुका है तथा इतना कमजोर हो गया है कि उन ताकतवर प्रांतीय नेताओं से भयाक्रांत है जिनका पार्टी की आधिकारिक स्थिति पर नियंत्रण है तथा उस अपार पैसे, जिस पर उनका नियंत्रण है, की बदौलत वे वरिष्ठ नेताओं को अपनी जेब में डाले घूमते हैं।

इस साल ने एक अन्य वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुये भी देखा है, और उनके (शेष पृष्ठ 5 पर)

पिता पर दोनों बच्चों के अपहरण का आरोप

जयपुर, 30 दिसंबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने छः साल और चार साल की दो संतानों का अपहरण कर अपने पास अवैध रूप से रखने के मामले में उनके पिता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा है कि, वह दोनों बच्चों को दस जनवरी को हाईकोर्ट में पेश करें।

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने बच्चों की मां कम्मूरी देवी मीना की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बच्चों को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये।

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश कम्मूरी देवी मीना की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि, याचिकाकर्ता के पति मुकेश कुमार ने कोविड लॉकडाउन में याचिकाकर्ता और उसकी दो नवजात संतानों को उसके अलवर (शेष पृष्ठ 5 पर)

यूक्रेन ने यू.एन. के तत्वावधान में एक "शांति प्रयास" का प्रस्ताव दिया

पर, यूक्रेन ने इस प्रयास में रूस को तभी शामिल करने की बात रखी, जब रूस बिना शर्त व पूर्णतया हथियार डाल दे

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। रूस ने यूक्रेन के इस विचार को "बेतुका" बताया है, इसकी खिल्ली उड़ाई है कि अगले वर्ष फरवरी में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक शांति शिखर सम्मेलन किया जाये। रूस ने कहा है कि वह ऐसे किसी सम्मेलन में तभी भाग लेगा जब यूक्रेन बिना किसी शर्त के तथा पूरी तरह आत्म समर्पण कर देगा।

कीव सरकार के इस शांति-प्रस्ताव को "पागलपन" तथा अमेरिका की "एक पी.आर.तिकड़म" बताया है, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, "हम इस पागलपन भर विचार को वॉशिंगटन की एक और चाल के रूप में देख रहे हैं क्योंकि इन दिनों वॉशिंगटन कीव सरकार को एक शांति समर्थक के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहा है।"

उन्होंने कहा, "हम 24 फरवरी, जिस दिन इस विशेष सैन्य कार्यवाही की

■ रूस ने यूक्रेन के प्रस्ताव को पागलपन व हास्यास्पद बताया, क्योंकि रूस के अनुसार, रूस के बिना, शांति वार्ता के क्या मायने हैं।

■ रूस के अनुसार, यूक्रेन का प्रस्ताव वॉशिंगटन की "पी.आर. एक्सरसाइज" है। वॉशिंगटन आजकल यूक्रेन व कीव की सरकार को "शांति दूत" की तरह चित्रित करने की कोशिश कर रहा है।

वर्षगाँठ है, के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.) के मंच पर एक प्रकार का "शांति सम्मेलन" के आयोजन के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कीव नेताओं की योजना के अनुसार, इससे ज़ैलेन्स्की की बेतुकी सोच के क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा, जिस बेतुकी सोच को उन्होंने "शांति के फॉर्मूले" के रूप में प्रस्तुत किया है। ज़खारोव ने जोर देते हुये कहा कि पूरे तथा बिना शर्त आत्म समर्पण की स्थिति में, इस प्रकार के किसी सम्मेलन में रूस की सहभागिता का विचार ही

कीव की कमजोर होती जा रही ताकत का प्रतीक है।

उन्होंने जोर देते हुये कहा, "इसके अलावा अन्य कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं है। वे (कीव) एक ऐसी स्थिति पर पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्हें ऐसे, बल्कि इससे भी ज्यादा पागलपन भर विचार आते हैं तथा इन विचारों का किसी न किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी आवरण में लपेट कर प्रस्तुत करते हैं लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक ही है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

द्रव्यवती नदी में गंदगी और अव्यवस्था

जयपुर, 30 दिसंबर (का.सं.)। जिले की स्थानीय लोक अदालत ने द्रव्यवती नदी में गंदगी व अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में जेडीए सचिव व टाटा प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर से 30 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। लोक अदालत ने यह आदेश ओमप्रकाश सैनी के प्रार्थना पत्र पर दिए।

■ लोक अदालत ने ओमप्रकाश सैनी की इस संबंध में दायर याचिका पर जे.डी.ए. और टाटा प्रोजेक्ट को नोटिस जारी किया।

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, अमानोशाह नाले की साफ-सफाई व उसे सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट को द्रव्यवती रिवर प्रोजेक्ट का काम दिया था। प्रोजेक्ट के तहत, नाले (शेष पृष्ठ 5 पर)